



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15042020-219056  
CG-DL-E-15042020-219056

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं. 97]	नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 15, 2020/चैत्र 26, 1942
No. 97]	NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 15, 2020/CHAITRA 26, 1942

---

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जॉच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2020

प्रकरण सं. एसएसआर.-06/2020

**विषय – चीन जन.गण. तथा थाइलैंड से पालिएस्टर के सभी पूर्ण रूप से ड्रान अथवा पूर्ण रूप से ओरिएंटेड यार्न/स्पिन ड्रान यार्न/ फ्लैट यार्न के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जॉच की शुरूआत ।**

**फा. सं. 7/9/2020-डीजीटीआर.—** 1. एसोसिएशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री (इसके पश्चात "आवेदक" के रूप में संदर्भित) ने घरेलू उत्पादकों की ओर से, मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मैसर्स वेलनौन पॉलिस्टर लिमिटेड, चीन जन.गण. तथा थाइलैंड (इसके पश्चात संबद्ध देशों के रूप में भी संदर्भित) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित पालिएस्टर के सभी पूर्ण रूप से ड्रान अथवा पूर्ण रूप से ओरिएंटेड यार्न/स्पिन ड्रान यार्न/ फ्लैट यार्न (इसके पश्चात "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" अथवा "संबद्ध वस्तु" के रूप में भी संदर्भित) के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जॉच के लिए समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (इसके पश्चात "अधिनियम" के रूप में भी संदर्भित) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाप्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संकलन तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (इसके पश्चात "नियमावली" के रूप में भी संदर्भित) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके पश्चात "प्राधिकारी" के रूप में भी संदर्भित) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।

2. आवेदक ने संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने तथा घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने की संभावना का आरोप लगाया है तथा संबद्ध देशों के मूल के अथवा से वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा और उसे जारी रखने का अनुरोध किया है।

### **पृष्ठभूमि**

3. चीन जन.गण. तथा थाइलैंड से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में प्राधिकारी द्वारा दिनांक 6 मई, 2008 की अधिसूचना सं.14/3/2008-डीजीएडी के माध्यम से मूल पाटनरोधी जाँच की शुरुआत की गई थी। प्रारंभिक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश दिनांक 23 जनवरी, 2009 की अधिसूचना सं.14/3/2008-डीजीएडी के माध्यम से की गई थी और उसे दिनांक 26 मार्च, 2009 की अधिसूचना सं. 29/2009-सीमाशुल्क (एडीडी) के माध्यम से लगाया गया था। तत्पश्चात, चीन जन.गण. और थाइलैंड पर दिनांक 29 सितंबर, 2009 की अधिसूचना सं.14/3/2008-डीजीएडी के माध्यम से निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए सिफारिश की गई थी और उसे दिनांक 11 नवंबर, 2009 की अधिसूचना सं.124/2009-सीमाशुल्क (एडीडी) के माध्यम से लगाया गया था।
4. एक निर्णायक समीक्षा (एसएसआर) जाँच की शुरुआत दिनांक 24 मार्च, 2014 की अधिसूचना सं. 15/3/2014-डीजीएडी के माध्यम से की गई थी। पाटनरोधी शुल्कों के विस्तार की सिफारिश दिनांक 22 सितंबर, 2015 की अधिसूचना सं. 15/03/2014-डीजीएडी के माध्यम से सिफारिश की गई थी और उसे केंद्र सरकार की अधिसूचना सं. 51/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 21 अक्टूबर, 2015 के माध्यम से लगाया गया था। वर्तमान पाटनरोधी शुल्क दिनांक 20 अक्टूबर, 2020 तक वैध है।

### **विचाराधीन उत्पाद**

5. विचाराधीन उत्पाद जो मूल जाँच पर प्रथम निर्णायक समीक्षा में था, पालिएस्टर के सभी पूर्ण रूप से ड्रान अथवा पूर्ण रूप से ओरिएंटेड यार्न/स्पिन ड्रान यार्न/ फ्लैट यार्न (गैर-टैक्सचर्ड और गैर-पीओवाई) तथा सीमाशुल्क के शीर्षक 5402.47 के प्रशुल्क विवरण के अनुरूप अन्य यार्न हैं। बाजार की वातचीत में इस उत्पाद को "पूर्ण रूप से ड्रॉन यार्न" अथवा एफडीवाई के रूप में सामान्य तौर पर जाना जाता है। संबद्ध वस्तुओं का तकनीकी विनिर्देशन उनकी मोटाई, दृढ़ता, चमक, रंग (जैसे आधा फीका, चमकदार, अत्यधिक चमकदार, पूरा फीका, डोप रंजित), विविधता और सिकुड़न के संबंध में परिभाषित किया गया है।

### **समान वस्तु**

6. आवेदक ने यह दावा किया है कि याचिकाकर्ता घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं में कोई ज्ञात अंतर नहीं है और यह कि ये दोनों समान वस्तु हैं और यह कि ये दोनों तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। इस कारण से, वर्तमान जाँच के उद्देश्य से, भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे संबद्ध वस्तुओं के "समान वस्तु" के रूप में माना जा रहा है।

### **घरेलू उद्योग**

7. यह आवेदन घरेलू उत्पादकों, मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मैसर्स वेलनौन पॉलिस्टर लिमिटेड, की ओर से एसोसिएशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने यह दावा किया है कि उन्होंने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का न तो आयात किया है और न ही इनका संबंध संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक या भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना पर विचार करते हुए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह आवेदन घरेलू उद्योग की ओर से अथवा उसके द्वारा इस नियमावली के नियम 2 (ख) नियम 5(3) में निहित प्रावधानों के संबंध में किया गया है।

### **पाटन के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना**

#### **i. चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य**

8. आवेदक ने यह दावा किया है कि चीन जन. गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य का निर्धारण इस नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 के संबंध में किया जाना चाहिए। आवेदकों ने इस नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-8(2) का उदाहरण दिया है और यह उल्लेख किया है कि चीन के उत्पादकों को इस

नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(3) के संबंध में संबंधित वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं। आवेदकों ने यह दावा किया है कि चीन के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण इस नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार किया जाना चाहिए। उत्पाद के मूल्य या ऐसे उचित तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था के विचाराधीन उत्पाद के निर्मित मूल्य या ऐसे तीसरे देश के भारत सहित अन्य देशों में कीमतें, आवेदक द्वारा न तो उपलब्ध कराई गई हैं और न ही यह जानकारी किसी भी सार्वजनिक स्रोत से प्राधिकारी के पास उपलब्ध है। उपर्युक्त को देखते हुए, चीन जन.गण. में संबंधित वस्तुओं का सामान्य मूल्य भारत में घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत के सबसे अधिक प्रभावी घटक तथा इसकी बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक खर्चों के आधार पर तय किया गया है।

#### ii. थाइलैंड के लिए सामान्य मूल्य

9. आवेदक ने यह दावा किया है कि थाइलैंड में उत्पादन की लागत से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं थे और भारत में उत्पादन की औसत लागत के आधार पर थाइलैंड में उत्पादन की लागत का दावा किया है। आवेदक ने उपर्युक्त तीसरे देश के संबंध में जानकारी नहीं दी है। यह जानकारी किसी सार्वजनिक स्रोत से प्राधिकारी के पास उपलब्ध नहीं है। तदनुसार, थाइलैंड के लिए सामान्य मूल्य उत्पादन की लागत, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों को विधिवत समायोजित करते हुए सबसे अधिक प्रभावी घरेलू उद्योग लागत के आधार पर भारत में उत्पादन की लागत के आधार पर तय किया गया है।

#### iii. निर्यात कीमत

10. प्राधिकारी ने वाणिज्यिक सूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) के लेनदेनवार आयात आंकड़ों के आधार पर संबंधित देशों के लिए संबंधित वस्तुओं के वास्ते निर्यात कीमत का परिकलन किया है। (चीन जन गण के लिए) समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतरदेशीय भाड़े संबंधी खर्च, पत्तन खर्च और बैंक प्रभारों तथा मूल्यवर्धित कर के लिए समायोजन किए गए हैं

#### iv. पाटन मार्जिन

11. उपर्युक्त में निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, पाटन मार्जिन का निर्धारण इस अधिनियम की धारा 9 क(1) (क) के अनुसार किया गया है।

#### क्षति का निरंतर जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना

12. आवेदक ने यह दावा किया गया है कि पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है।

#### निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरुआत

13. आवेदक के विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर, और स्वयं को संतुष्ट करके, प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, प्राधिकारी एतद्वारा संबंधित देशों के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित संबंधित वस्तुओं के संबंध में लागू शुल्कों को लगातार लगाए जाने की आवश्यकता की समीक्षा करने और इस तथ्य की जाँच करने कि क्या मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने पर घरेलू उद्योग को क्षति और पाटन के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है, अधिनियम की धारा 9ए(5) और इस नियमावली के नियम 23 (1 ख) के संबंध में निर्णायक समीक्षा जाँच आरंभ करते हैं।

#### संबद्ध देश

14. जाँच के उद्देश्य से संबद्ध देश चीन जन.गण. तथा थाइलैंड हैं।

#### जाँच की अवधि

15. प्राधिकारी 1 जनवरी, 2019 से 30 दिसंबर, 2019 तक (12 माह) के रूप में वर्तमान जाँच के लिए जाँच की अवधि (पीओआई) का प्रस्ताव करते हैं। क्षति की जाँच की अवधि में 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017; 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018; 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019; और जाँच की अवधि शामिल होगी।

#### प्रक्रिया

16. इस समीक्षा जाँच में दिनांक 22 सितंबर, 2015 की अधिसूचना सं. 15/3/2014 -डी जी ए डी के माध्यम से प्रकाशित अंतिम जाँच परिणाम के सभी पहलू शामिल होंगे जिसमें चीन जन गण और थाइलैंड से पालिएस्टर के सभी पूर्ण रूप से

ड्रान अथवा पूर्ण रूप से ओरिएण्टेड यार्न/स्पिन ड्रान यार्न/ फ्लैट यार्न के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क के विस्तार की सिफारिश की गई है। प्राधिकारी पाटनरोधी और क्षति के संभावित विश्लेषण भीकरेगा।

17. उपर्युक्त नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 तथा 20 के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित इस समीक्षा में लागू रहेंगे।

#### **सूचना प्रस्तुत करना**

18. संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों, भारत में इसके दूतावास के माध्यम से उनकी सरकारों, संबद्ध वस्तुओं से संबंधित भारत में ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे दी गई समयसीमा के भीतर निर्धारित रूप में और ढंग से सभी संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए उन्हें सक्षम बनाने हेतु पृथक् रूप से सूचित किया जा रहा है।
19. अन्य कोई भी हितबद्ध पक्षकार नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित स्वरूप एवं तरीके से जांच से संगत अपने अनुरोध भी कर सकते हैं।
20. सूचना/अनुरोध निम्नलिखित को प्रेषित किए जा सकते हैं :-

#### **निर्दिष्ट प्राधिकारी**

#### **व्यापार उपचार महानिदेशालय**

#### **वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**

#### **वाणिज्य विभाग**

**चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग,**

**नई दिल्ली- 110001**

21. प्राधिकारी के समक्ष किसी गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार से यह अपेक्षित है कि वे अन्य पक्षकारों को उस अनुरोध का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराएं।

#### **समय-सीमा**

22. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर, वर्तमान जाँच से संबंधित कोई भी जानकारी लिखित रूप इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर उपरोक्त पते पर प्राधिकारी तक पहुँच सके। यदि कोई सूचना निर्धारित समयसीमा के भीतर प्राप्त नहीं होती हो अथवा प्राप्त सूचना पूर्ण नहीं हो, तब प्राधिकारी इस नियमावली के अनुसार, रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपनी जांच परिणामों को रिकॉर्ड कर सकते हैं।
23. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित(हित की प्रकृति सहित) के बारे में सूचना दें और उपर्युक्त समयसीमा के भीतर अपनी प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करें।

#### **गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

24. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले अथवा गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार से यह अपेक्षित है कि वे इस नियमावली के नियम 7(2) तथा इस संबंध में जारी किए गए व्यापार नोटिसों के संबंध में उसका एक अगोपनीय पाठ साथ-साथ प्रस्तुत करें। उपर्युक्त का पालन नहीं करने पर प्रत्युत्तर/अनुरोधों को अस्वीकार किया जा सकता है।
25. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली के उत्तर सहित कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्टों/अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकारों को, यदि उसके किसी भाग के संबंध में "गोपनीयता" का दावा किया गया है तो, दो अलग-अलग सैटों में उन्हें प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

i. एक सैट गोपनीय रूप में चिन्हित (शीर्षक, पृष्ठों की संख्या, विषय सूची आदि सहित), और

ii. दूसरा सैट अगोपनीय रूप में चिन्हित (शीर्षक, पृष्ठों की संख्या, विषय सूची आदि सहित)।

26. "गोपनीय अथवा अगोपनीय" अनुरोधों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" के रूप में स्पष्ट से चिन्हित किया जाना चाहिए। ऐसे चिन्ह के बिना कोई अनुरोध प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी

अन्य हितवद्ध पक्षकारों को उन अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। दोनों पाठों की सॉफ्ट प्रतियाँ प्रत्येक की दो (2) सेटों में हार्ड कॉपी के साथ प्रस्तुत किया जाना भी अपेक्षित होगा।

27. गोपनीय पाठ में वे सभी सूचना निहित होंगी जो गोपनीय प्रकृति की हैं और/अथवा अन्य प्रकार की सूचना है जो इस प्रकार की सूचना देने वाले व्यक्ति गोपनीय के रूप में दावा करते हैं। उस सूचना के लिए, जिसके संबंध में गोपनीय होने का दावा किया गया है अथवा वह सूचना जिसके संबंध में अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया गया है, सूचना देने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वे दी गई सूचना के साथ-साथ सही कारण का विवरण उपलब्ध कराएं कि क्यों इस प्रकार की सूचना को प्रकट नहीं किया जा सकता है।
28. अगोपनीय पाठ के लिए यह अपेक्षित है कि वह गोपनीय सूचना अधिमानतः अथवा कवर किया (यदि अनुक्रमण संभव नहीं हो) और उस सूचना जिसके संबंध में गोपनीयता का दावा किया गया हो, के आधार पर सारांश किए जाने के साथ गोपनीय पाठ की एक प्रतिकृति हो। अगोपनीय सारांश विस्तृत व्यौर के साथ होने चाहिए जिसमें कि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के अर्थ को तर्कसंगत तरीके से समझा जा सके। हालांकि, आपवादिक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार यह उल्लेख कर सकते हैं कि इस प्रकार की सूचना का सारांश नहीं किया जा सकता है और कारणों का एक विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार अवश्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि क्यों इसका सारांश किया जाना संभव नहीं है।
29. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने पर गोपनीयता के लिए अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हों कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा यदि सूचना देने वाली इस सूचना को सार्वजनिक करने के लिए या तो इच्छुक नहीं हैं अथवा सामान्य रूप में या सारांश रूप में इसके प्रकटन के लिए अधिकृत करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, तब प्राधिकारी इस प्रकार की सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।
30. उसके सार्थक अगोपनीय रूपांतर के बिना अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में सही कारण का विवरण दिए बिना कोई अनुरोध प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।
31. प्राधिकारी संतुष्ट होने पर और दी गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता स्वीकार करने पर उस सूचना को प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट अधिकरण के बिना किसी पक्षकार को उसे प्रकट नहीं करेंगे।

#### **सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**

32. इस नियमावली के नियम 6(7) के संबंध में, कोई भी हितवद्ध पक्षकार अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय पाठ वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

#### **असहयोग**

33. यदि कोई हितवद्ध पक्षकार सूचना तक पहुंच की अनुमति देने से इंकार करता है अथवा अन्य प्रकार से उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है या इस जांच में पर्याप्त रूप से बाधा पहुंचाता है तब प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम को रिकॉर्ड कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को ऐसी सिफारिशें, जिसे वे उचित मानते हों, कर सकते हैं।

भूपिन्दर एस. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

### **MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

### **INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th April, 2020

Case No. SSR-06/2020

**Subject: - Initiation of Sunset Review investigation concerning imports of All Fully Drawn or Fully Oriented Yarn/ Spin Drawn Yarn/ Flat Yarn of Polyester from China PR and Thailand.**

**F.No.7/9/2020-DGTR.**—1. Association of Synthetic Fibre Industry (hereinafter referred to as the “Applicant”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”), on behalf of the domestic producers namely, M/s. Reliance Industries Limited and M/s. Wellknown Polyesters Limited, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection

of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred as the “Rules”), for Sunset Review anti-dumping investigation concerning imports of All Fully Drawn or Fully Oriented Yarn/ Spin Drawn Yarn/ Flat Yarn of Polyester (hereinafter also referred to as “product under consideration” or “PUC” or “subject goods”), originating in or exported from China PR and Thailand (hereinafter also referred to as the “subject countries”).

2. The Applicant has alleged likelihood of continuation or recurrence of dumping of subject goods, originating in or exported from the subject countries and consequent injury to the domestic industry and have requested for sunset review and continuation of the anti-dumping duty imposed on the imports of subject goods, originating in or exported from the subject countries.

#### **Background**

3. The original anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from China PR and Thailand was initiated by the Authority vide Notification No.14/3/2008-DGAD dated 6<sup>th</sup> May, 2008. Preliminary anti-dumping duties were recommended vide Notification No. No.14/3/2008-DGAD dated 23<sup>rd</sup> January, 2009 and imposed vide Notification No. 29/2009-Customs (ADD) dated 26<sup>th</sup> March, 2009. Thereafter, definitive anti-dumping duties were recommended for imposition on China PR and Thailand vide Notification No. No. 14/3/2008-DGAD dated 29<sup>th</sup> September, 2009 and the same were imposed vide Notification No. 124/2009-Customs (ADD) dated 11<sup>th</sup> November, 2009.
4. A Sunset Review (SSR) investigation was initiated vide Notification No. 15/03/2014-DGAD dated 24<sup>th</sup> March, 2014. The extension of anti-dumping duties was recommended vide Notification No. 15/03/2014-DGAD dated 22<sup>nd</sup> September, 2015 and the same was imposed by the Central Government vide Notification No. 51/2015-Customs (ADD) dated 21<sup>st</sup> October, 2015. The current anti-dumping duty is valid up to 20<sup>th</sup> October, 2020.

#### **Product under Consideration**

5. The product under consideration, as in the original investigation and the first Sunset Review, is fully drawn/ fully oriented yarn/ spin drawn yarn/ flat yarn of polyester (non-textured and non-POY) and other yarns conforming to the tariff description of Customs Heading 5402.47. The product in market parlance is generally known as ‘Fully Drawn Yarn’ or FDY. Technical specifications of the subject goods are defined in terms of their deniers, tenacities, lustres, colours (like semi dull, bright, super bright, full dull, Dope dyed), cross section and shrinkage.

#### **Like Article**

6. The Applicant has claimed that there is no known difference in the subject goods produced by the petitioning domestic producers and those exported from subject countries and that the two are like articles and are technically and commercially substitutable. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the petitioning domestic producers are being treated as ‘Like Article’ to the subject goods being imported from the subject countries.

#### **Domestic Industry**

7. The application has been filed by Association of Synthetic Fibre Industry on behalf of the domestic producers namely, M/s. Reliance Industries Limited and M/s. Wellknown Polyesters Limited. The Applicant has claimed that the petitioning domestic producers have neither imported the subject goods from the subject countries nor are related to any exporter or producer of subject goods in the subject countries or any importer of the PUC in India. Considering the information on record, the Authority notes that the application has been made by or on behalf of the domestic industry in terms of the provisions contained in Rule 2 (b) and Rule 5 (3) of the Rules.

#### **Likelihood of continuation or recurrence of dumping**

##### **i. Normal Value for China PR**

8. The Applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and the normal value should be determined in terms of paragraph-7 of Annexure I of the Rules. The Applicants have cited Para 8(2) of Annexure I of the Rules and have stated that the Chinese producers should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry producing the subject goods in terms Para 8(3) of Annexure I of the Rules. The Applicants have claimed that for China, normal value should be determined in accordance with para 7 and 8 of Annexure I of the Rules. The prices or constructed value of the product under consideration in the appropriate market economy third country or the prices from such third country to other countries, including India, has neither been made available by the Applicant nor is this information available with the Authority from any public source. In view of the above, the normal value of the subject goods in China PR has been constructed based on the cost of production and associated selling, general and administrative expenses involved in manufacture of PUC by the most efficient petitioning domestic producer in India.

**ii. Normal Value for Thailand**

9. The Applicant has claimed that the data relating to cost of production in Thailand is not available and has claimed the cost of production in Thailand on the basis of average cost of production in India. The Applicant has not provided information with regard to the appropriate third country. This information is also not available with the Authority from any public source. Accordingly, the normal value for Thailand has been constructed on the basis of cost of production in India based on the cost of production and associated selling, general and administrative expenses involved in manufacture of PUC by the most efficient petitioning domestic producer.

**iii. Export Price**

10. The export price for subject goods for the subject countries has been computed based on the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) transaction-wise import data. Adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, commission, inland freight expenses, port expenses, bank charges and VAT (for China PR).

**iv. Dumping Margin**

11. Considering the normal value and export price determined as above, dumping margin has been determined, in accordance with Section 9 A(1)(a) of the Act.

**Likelihood of continuation or recurrence of Injury**

12. The Applicant has claimed that the cessation of anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of injury.

**Initiation of Sunset Review**

13. On the basis of the duly substantiated application of the Applicant, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence substantiating the likelihood of continuation/ recurrence of dumping and injury, and in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 (1B) of the Rules, the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from subject countries to examine whether the expiry of existing anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

**Subject Countries**

14. For the purpose of the investigation, the subject countries are China PR and Thailand.

**Period of investigation**

15. The period of investigation (POI) for the present investigation is from 1<sup>st</sup> January 2019 to 31<sup>st</sup> December, 2019 (12 Months). The injury investigation period will cover the periods 1<sup>st</sup> April, 2016- 31<sup>st</sup> March 2017; 1<sup>st</sup> April 2017- 31<sup>st</sup> March, 2018; 1<sup>st</sup> April, 2018- 31<sup>st</sup> March, 2019, and the POI.

**Procedure**

16. The review investigation will cover all aspects of the final findings published vide Notification No. 15/3/2014-DGAD dated 22<sup>nd</sup> September, 2015 recommending extension of anti-dumping duty on imports of All Fully Drawn or Fully Oriented Yarn/ Spin Drawn Yarn/ Flat Yarn of Polyester from China PR and Thailand. The Authority will also undertake likelihood analysis of dumping and injury.
17. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules shall be mutatis mutandis applicable in this review.

**Submission of Information**

18. The known exporters in the subject countries, their Governments through their embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
19. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.
20. The information/ submission may be submitted to:

**The Designated Authority**  
**Directorate General of Trade Remedies**  
**Ministry of Commerce & Industry**  
**Department of Commerce**  
**4th Floor, Jeevan Tara Building, 5 Parliament Street**  
**New Delhi – 110001**

21. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties

**Time Limit**

22. In view of the special circumstances arising from COVID-19 pandemic, any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above within sixty days from the date of issue of this notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
23. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

**Submission of information on confidential basis**

24. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.
25. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:
- i. one set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and
  - ii. the other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).
26. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies in two (2) sets of each.
27. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
28. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
29. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
30. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.



31. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

**Inspection of Public File**

32. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

**Non-cooperation**

33. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

BHUPINDER S. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority